



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - **13850** वर्ष **2026**

विवेक सक्सेना उर्फ शानू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शक्ति दुबे, विनय कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 597 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, पुलिस थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु योजित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 06.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को मृतक प्रमोद सक्सेना को चोट कारित करने की भूमिका आरोपित की गई है, परंतु विचारण के अनुक्रम के दौरान, प्रथम सूचनादाता, जो कि मृतक की पत्नी है, ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया, अतएव, उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अन्य अभियोजन गवाहों- विनोद कुमार तथा प्रदीप कुमार सक्सेना, जो कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतक के सगे भाई हैं, का विचारण न्यायालय में अभियोजन गवाह-2 तथा अभियोजन गवाह-3 के रूप में परीक्षण किया गया परंतु उन्होंने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अभियोजन गवाह-4 श्रीमती अनीता, अभियोजन गवाह-5 श्रीमती रजनी तथा अभियोजन गवाह-6 श्रीमती शालिनी देवी, जो मृतक की निकट संबंधी थीं, को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है तथा वर्तमान मामले में उसकी दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अंत में यह कथन है कि आवेदक 07.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है और यदि, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, अतएव, वह जमानत पर रिहा होने का अधिकारी नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने के पश्चात, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदक जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है।
6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त आवेदक- विवेक सक्सेना उर्फ शानू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना, उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय के मत में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।